आवासन मंडल का बड़ा तोहफा

मंडल अध्यक्ष भास्कर ए. सावंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया निर्णय

आवासन कर्मचारियों के लिए लॉन्च होगी मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना

महानगर संवाददाता

जयपुर। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि मंडल द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों और आमजन को बड़ा तोहफा देते हुए प्रताप नगर में मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना और राज्य के 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इन योजनाओं की लॉन्चिंग एक माह के भीतर मुख्यमंत्री स्तर पर करवाई जाएगी। अरोड़ा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में प्रत्येक व्यक्ति का सपना है कि उसका अपना घर हो। उनके इस सपने को साकार करने के लिए मंडल ने प्रत्येक वर्ग की जरूरतों के हिसाब से उचित कीमत पर आवासीय योजना तैयार की गई है। मंडल अध्यक्ष भास्कर ए. सावंत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया।

आवासन आयुक्त अरोड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना में प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार 674 फ्लैट्स निर्मित किए जाएंगे। योजना में 10 लाख 90 हजार रुपए में 632 वर्गफीट में निर्मित 2 बीचएचके फ्लैट, 15 लाख 70 हजार रुपए में 882 वर्गफीट क्षेत्र में निर्मित 2 बीचएचके फ्लैट और 21 लाख रुपए में 1097 वर्ग फीट में निर्मित 3 बीचएचके फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना में पूर्व में लॉन्च की गई मुख्यमंत्री राज्य सहायक कर्मचारी योजना के आवेदकों को भी शामिल किया जाएगा। इस योजना के आस-पास स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं। उल्लेखनीय है कि मंडल द्वारा इससे पूर्व शिक्षकों और कांस्टेबलों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक व प्रहरी आवासीय योजना लॉन्च की गई थी, जिसमें 576 फ्लैटों के विरुद्ध 700 से अधिक आवेदकों ने पंजीकरण कराया है।

किस्तों पर नहीं लगेगा जीएसटी

अरोड़ा ने बताया कि '10 प्रतिशत दीजिए घर प्रवेश कीजिए' योजना में किस्तों पर जीएसटी लगने के संबंध में भ्रम की स्थिति थी। अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में जीएसटी विशेषज्ञों से चर्चा कर ली गई है, ये चूंकि पूर्ण निर्मित मकान हैं, इसलिए जीएसटी न तो किस्तों पर और न ही डिमांड पर लगेगा, अब ये मकान आमजन को और भी सस्ते उपलब्ध होंगे। मंडल अध्यक्ष सावंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में 27 प्रकरणों पर विचार किया गया। इस बैठक में मुख्य नगर नियोजक आर.के. विजयवर्गीय, मुख्य अभियंता के.सी. मीना, जी.एस. बाघेला, अतिरिक्त नगर नियोजक अनिल माथुर, उप नगर नियोजक संत सरन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सभी श्रेणी में 11 हजार 250 आवास होंगे उपलब्ध

आयुक्त अरोड़ा ने बताया कि 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं लॉन्च की जाएंगी। ये योजनाएं जयपुर के सिरोली, वाटिका, महला, शाहपुरा, उदयपुर के दक्षिण विस्तार एवं देवारी, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, टोंक के निवाई, सिरोही के आबूरोड, अजमेर के नसीराबाद, किशनगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लॉन्च होंगी। इन योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग-अ, मध्यम आय वर्ग-ब व उच्च आय वर्ग के लिए 11 हजार 250 आवास उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत देय लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान आवासन मंडल के 50 वर्ष के इतिहास में इतनी योजनाएं एक साथ कभी भी लॉन्च नहीं की गई हैं। उन्होंने बताया कि मंडल द्वारा आगामी बोर्ड बैठक में इन योजनाओं को अनुमोदन करवाकर शीघ्र लॉन्च किया जाएगा।

आवासन मंडल मुख्यालय में राज्य का पहला सेनेटाइजेशन स्टेशन स्थापित

आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बुधवार को आवासन मंडल मुख्यालय में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश के पहले सुव्यवस्थित सेनेटाइजेशन स्टेशन का उद्घाटन किया। अरोड़ा ने बताया कि मंडल कार्यालय में आने वाले कर्मचारियों और आमजन को कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए सेनेटाइजेशन स्टेशन की स्थापना की गई है। अब आवासन मंडल के सभी कार्यालयों में भी सेनेटाइजेशन स्टेशन बनाए जाएंगे। अरोड़ा ने बताया कि अगर मंडल की योजनाओं में मोहल्ला समितियों या रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटियों द्वारा इस तरह का सेनेटाइजेशन स्टेशन बनाया जाता है तो आवासन मंडल उन्हें 25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देगा।